सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहिम): (क) दूरदर्शन, धारावाहिकों को स्वीकृति प्रदान करते समय निम्नलिखित मानकों का अनुपालन करता है:—

(1) कथावस्तु तथा इसकी समसामयिक प्रासंगिकता।

(2) विषय वस्तु का विवेचन।

(3) तकनीकी कर्मी दल की समग्र सक्षमता; तथा

(4) दूरदर्शन की कार्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं के प्रति प्रासंगिकता।

(ख) और (ग) जी, हां। दूरदर्शन की नई प्रायोजकता स्कीम के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत उन निर्माताओं जिनके प्रस्ताव रद्द कर दिए गए थे, की अपील का प्रावधान है जिनकी एव पुनरीक्षा समिति द्वारा जांच की जा रही है जिसमें महानिदेशक, दूरदर्शन और दूरदर्शन द्वारा बनाए गए पैनल में से कम से कम तीन गैर-सरकारी विशेषज्ञ (उन गैर-सरकारी विशेषज्ञों को छोड़ कर जिन्होंने पहले प्रस्ताव पर विचार किया था) शामिल हैं।

(घ) ब्यौरा निम्नानुसार है:—

1995	:	शून्य
1996	:	तीन

हिमाचल प्रदेश में हवाई पट्टियों के विकास की योजना

341. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश मे भुन्तर (कुल्लू), गग्गल (कांगड़ा) और जुब्बल (शिमला) में स्थित हवाई पट्टियों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहिम): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की हिमाचल प्रदेश में गग्गल, भुंतर और शिमला में हवाई पट्टियों के विकास की योजनाएं हैं। कुल्लू में विद्यमान हवाई पट्टी के पुनः सतहीकरण के लिए 146 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और ब्यास नदी के साथ-साथ एक बांध और चारदीवारी के निर्माण के लिए 36.89 लाख रुपए की राशि आवंटित की गयी है। गग्गल हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की धावनपथ को 3900 फुट से बढ़ाकर 4500 फुट तक करने की योजना है और शिमला में, 53 लाख रुपए की अनुमानित लागत से धावनपथ को 3800 फुट से बढ़ाकर 4100 फुट करने का कार्य प्रगति पर है। कार्य के दिसम्बर, 1996 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

मध्य प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालयों का खोला जाना

342. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय की शाखाएं वर्ष 1991-92 से 1994-95 तक प्रति वर्ष कहां-कहां खोली गई हैं;

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 में नई शाखाएं कहां-कहां खोले जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं,

(ग) क्या रायगढ़ जिले के जगपुर नगर में इस तरह के किसी शाखा कार्यालय को खोले जाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Raids conducted by Custom and Central Excise Department

343. SHRI AJIT P.K. JOGI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of raids conducted by Custom and Central Excise Departments during the last three years;

(b) the total amount of cash and goods seized in these raids;

(c) the number of cases involved in these raids which have since been disposed of; and

(d) the State-wise amount realised by Government as custom duty and excise duty and also as penalty thereon?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Investmentby NRI*s**

344. SHRI JANARDHANA POOJ ARY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) the total investment by NRI*s in India as on 30th June, 1996;

(b) whether Government arc taking any fresh measures to attract NRI*s to invest more in the country; if so, the details thereof; and

(c)* if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AF-* FAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The NRI investment flows during 1991 to 31.3.96 (latest available) as pro vided by Reserve Bank of India (RBI) total Rs. 4391 crores.

(b) and (c) In an effort to streamline the existing investment facilities and to attract more investment from NRI*s, a Working Group was set up by RBI which has since submitted its recommendations. The recommendations include revamping of the existing investment schemes with reference to their relevance in the liberalised economy and steps towards simplification of approval procedures. Government has considered and concurred with a number of these recommendations which have been operationalised by RBI as per the Statement given below.

Statement

1. General permission to OCBs for sale of share acquired under protfolio investment schemes.

2.General permission for sale of shares by NRIs/OCBs acquired on repatriation basis under direct investment schemes provided sale is through recognised stock Exchange.

3. Simplification of the procedure for grant of final permission for issue/export of shares to NRIs.

4. General permission to NRIs for subscription to the Memorandum and Articles of Association of Indian companies, (which earlier covered only companies engaged in industrial activities), has been extended to all companies irrespective of the activity undertaken by the company.

5. Rasing of formalities for opening Non-Resident Ordinary (NRO) Account.

6. Disperation of the requirement of prior permission by RBI for remittance of sale proceeds of shares (net of taxes) to offset loans raised abroad on security of shares of Indian companies.

7. Permission to Authorised Dealers (ADs) to extend rupee loans to NRIs for acquisition of residential houses in India conforming to the terms and conditions followed by Housing Finance Companies.

8. Permission to Indian Companies to grant housing loans to NRI Staff deputed abroad under the company*s Staff Housing Loan Scheme subject to repayment in foreign exchange.

9. General permission to Indian Companies for payment of interest on delayed refund of share subscription.

10. Safe custody of securities on behalf of NRIs/OCBs permitted to be done by institutional custodians beside ADs.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri V. Narayanasmy): In the Chair.

12.00 Noon

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notifications of the Ministry of Finance

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue) under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944:—

(1) Ad-hoc Eaemption Order No. *38* 396-CX, dated 19 March, 19%, exeoptatf certain excisable goods from all the duties of excise leviable thereon.

(2) Ad-hoc Exemption Order No. 4/ S96-CX, dated 2 April, 1996, granting exemption to iron, steel and cement.

(3) Ad-hoc Exemption Order No. 41/ 696-CX, dated 2nd April, 1996, exempting certain hospital laun-